out autonomous bodies and guarantee organisations under the Pension Scheme of 1972 respectively, if so, what are the details of the proposal?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) of THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) A pension scheme is in operation since 24-10-81 for the employees of Export Inspection Council and Export Inspection Agencies. As regards extension of the Pension Scheme to the autonomous and guarantee organisations, no general decision has been taken by the Government. As and when such a decision is taken, the question of extending the Pension Scheme for the employees of other autonomous bodies and guarantee organisations functioning under the administrative control of the Ministry of Commerce will be examined.

नये नवोदय विद्यालय खोलना

1124. **श्री भंवर लाल पंवार:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में और अधिक नवोदय विद्यालय खोलने की सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): नवोदय विद्यालय की योजना में देश के प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोलने की परिकल्पना की गई है । सबसे पहले राज्य सरकार की पेशकश के आधार पर स्थान का चयन किया जाता है । विद्यालय चलाने के लिए संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रारम्भ में निःशुल्क तीस एकड़ भूमि और भवन तथा अन्य अवस्थापनाओं की व्यवस्था की जाती है। जहां तक संभव होगा इन विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। अब तक देश में 275 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। नवोदय विद्यालय खोलना समग्र संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासनिक मूर्दों के अतिरिक्त संबंधित राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार के प्रस्ताव पर आधारित होता है जिसे प्रारम्भ में 2–3 वर्षों के लिए विद्यालय चलाने हेतु निःशुल्क 30 एकड़ उपयुक्त भूमि, पर्याप्त भवन और अन्य अवस्थापनाओं की व्यवस्था करनी होती है ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

1125. **श्री भंवर लाल पंवार:** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 1 सितम्बर, 1988 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 4406 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति हेतु पिछड़े वर्गों के कितने पात्र व्यक्तियों के नाम विचारार्थ भेजे थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्त किया गया था ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय कितने न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई और उनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़े वर्गों से कितने न्यायाधीश संबंधित थे ; और

(ग) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियों पर नियुक्तियां करते समय सरकार उपरोक्त स्थिति पर विशेष ध्यान देने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्): (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 124 और 217 के अनुसार की